कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक
प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल

कला संपादक
धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क
वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क
InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QSD I : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

भूटान संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री का भाषण

भूटान और भारत की सांझी विरासत हमें जोड़ती है.................................. 7

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

नरेन्द्र मोदी.. 11
सुषमा स्वराज.. 13
कीरेन रिजीजू.. 14
राजीव प्रताप रूड़ी.. 15
अरुण जेटली.. 17
मुख्तार अब्बास नकवी.. 18
जगत प्रकाश नड्डा.. 19

विशेष बातचीत

रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन).. 21

लेख

अराजकता का ठिकाना
– **बलबीर पुंज**.. 23
निर्मल गंगा की नई आस
– **हृदयनारायण दीक्षित**.. 25
बिहार में फिर जंगलराज
– **संजीव कुमार सिन्हा**.. 27

अन्य

दिल्ली : ई-रिक्शों का हुआ उद्धार, करोड़ों को मिलेगा रोजगार............... 30

~~~~~~☯☯☯~~~~~~

रथ यात्रा
जगन्नाथ पुरी

~~~~~~☯☯☯~~~~~~

29 जून 2014

देश के चारों धामों में से एक
उड़ीसा में स्थित धाम में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा

बोध कथा

शहीद का सवाल

शहीद करतार सिंह सराभा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी मुहिम अमेरिका में शुरू की थी। वे वहां भारतीयों को एकजुट करते थे। इससे अमेरिका की पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सराभा वहां से कोलंबो जा पहुंचे। फिर वहां से किसी तरह बचते-बचाते स्वदेश लौट आए और एक सैनिक छावनी में पहुंचे। छावनी में वे भारतीय सैनिकों को विदेशी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की प्रेरणा देने लगे।

एक दिन उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज जज ने राजद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुना दी। एक दिन उनके दादा उनसे जेल की कोठरी में मिलने आए और समझाते हुए बोले, 'बेटा, अभी तेरी उम्र बहुत कम है। घर में सबका बुरा हाल है। मैंने सुना है कि यदि तुम वायसराय के नाम माफीनामा लिख दोगे तो शायद फांसी से बच जाओगे।' दादा की बात सुनकर सराभा ने सवाल किया, 'दादाजी, हमारे गांव में रज्जू नाम का एक व्यक्ति था। वह आजकल कहां है?'

दादा बोले, 'बेटा, वह पिछले दिनों प्लेग से मर गया।' इसके बाद सराभा ने अपने एक रिश्तेदार के बारे में पूछा तो दादाजी बोले, 'वह हैजे से मर गया।' इस पर सराभा ने कहा, 'दादा जी, आप क्या चाहते हैं कि आपका पौत्र अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए न मर कर किसी बीमारी से बिस्तर पर पड़ा-पड़ा मर जाए?' दादा अपने पौत्र की राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे शब्द सुनकर चुप रह गए और उसके प्रति नतमस्तक हो गए। नवंबर 1916 में राष्ट्रभक्त सराभा को फांसी दे दी गई। महज 19 वर्ष की उम्र में सराभा ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

संकलन : रेनू सैनी

(नवभारत टाइम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र

उन्होंने कहा था...

आर्थिक लोकतंत्र

भारतीय चेतना प्रकृति से प्रजातंत्रीय है और आज का युग भी प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है। राजनीति के क्षेत्रों में यह प्रजातंत्र का भाव बहुत कुछ स्पष्ट होकर आया है तथा अब आर्थिक क्षेत्र में भी इसी प्रजातंत्र का उदय हो रहा है। राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार शासन की संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेंद्रीकरण करके अर्थव्यवस्था का निर्माण और संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मकता क्षमता को व्यक्त होने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक इसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को कुचलकर रख देने का नहीं, अपितु उसको व्यक्त होने का पूरा अवसर प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए।

-पं. दीनदयाल उपाध्याय

भरोसा नहीं टूटने देंगे

दस वर्ष की यूपीए सरकार को हटाने का काम देश की जनता ने किया है। नई सरकार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी है। यह जनता की सरकार है। जनता को अपनी सरकार चलाने में पूरी मदद करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना कि यूपीए सरकार ने देश का खजाना खाली कर दिया है और देश की माली हालत खराब है, इस बात में पूरी सच्चाई है। देश में पिछले दस वर्षों में सरकार नाम की कोई चीज थी ही नहीं। देश को कभी एहसास नहीं हुआ कि देश में कोई सरकार है।

भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में कठपुतली प्रधानमंत्री है। इस खबर से भारत को दस वर्षों में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने छह वर्ष के कार्यकाल में भारत की साख और धाक दोनों बढ़ाई थी। विश्व में भारत मस्तक ऊंचा कर चलने लगा था। लेकिन उस समय की स्थिति को यूपीए सरकार बरकरार नहीं रख पाई।

गत दस वर्षों में देशहित के निर्णय छोड़कर सभी निर्णय लिए गए। सारे मंत्री घोटाले करने में या घोटालेबाजों को बचाने में लगे रहे। संसदीय इतिहास में गत दस वर्षों में जो घोटाले हुए वह पूर्व में कभी नहीं हुआ। मजेदार मामला यह रहा कि घोटालों के उजागर होने पर कभी भी तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई चिंता या शर्म महसूस की हो, ऐसा नहीं हुआ। उल्टे इन घोटालेबाजों को बचाने में लगे रहे। निरकुंश हो चुकी यूपीए सरकार में 'संसद' की कार्यवाही कभी भी ढंग से नहीं चली। यूपीए सरकार में 'संसद सत्रों' की हालत बहुत गंभीर थी। सत्र का सत्र हंगामों में डूबा रहता था।

देश की जनता यूपीए सरकार से बुरी तरह त्रस्त थी। जनता को जब इस बात का एहसास नहीं हो कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे पास है या हमारे लिए है तो उस सरकार का सरकार में बने रहने का कोई अर्थ नहीं होता। यूपीए सरकार में ऐसा ही हुआ। एक बात और हुई कि यूपीए सरकार ने जनता को सिर्फ वोटर की नजरों से देखना शुरू किया। जनता जनार्दन होती है। 'वोटर' समझने पर सरकार का व्यवहार सौदेबाजी का होता है। यूपीए सरकार ने जो भी निर्णय लिए वह सभी वोटरों की निगाह से लिए। 'वोट' को सामने रखकर जो भी निर्णय होगा वह 'दल' के लिए हो सकता है, पर देश के लिए नहीं हो सकता।

भाजपा नीत एनडीए सरकार और यूपीए सरकार में मूल अंतर इसी बात का है कि एनडीए के सामने पहले देश है और देश के नागरिक। यही कारण है कि अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वह सभी देशहित में है। भाजपा का साफ कहना है कि पहले देश, बाद में दल।

परिवर्तन की बयार देश में बहने लगी है। जनता के सामने देश की वर्तमान हालत का सच रखना ही होगा। देश सिर्फ सरकार को नहीं चलाना होता बल्कि देश चलाने का दायित्व एक-एक नागरिक का होता है। तात्कालिक लाभ के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार ने अनाप-शनाप निर्णय लिए। यही कारण था कि देश हर क्षेत्र में पिछड़ता गया। अब स्थिति बदल रही है। देश की वास्तविक स्थिति देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया गया है।

पटरी से उतरी गाड़ियों को पटरी पर लाने के लिए एक नहीं अनेक कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देशहित में कुछ कड़वे निर्णय लेने पड़ेंगे। उन्होंने जनता को गुमराह नहीं किया और न ही उन्हें बहलाया। स्थिति सुधारने के लिए प्रारंभ में कुछ कठोर निर्णय लेना जरूरी हो गया है। लेकिन धीरे-धीरे देश को पटरी पर लाया जाएगा। देश में प्रशासन की और कर्मचारियों की कार्य संस्कृति में बदलाव की दिशा में अनेक कदम उठाए। कार्य संस्कृति में सुधार

प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रमादित्य को नौसेना को समर्पित किया

गत 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को गोवा के तट पर नौसेना को समर्पित किया और कहा कि भारत न तो किसी देश को धमकी देगा और न ही भारत किसी देश से भयभीत होगा- हम किसी को न आंख दिखाएंगे, ना आंख झुकाएंगे, दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की बहादुरी और इनके समर्पण भाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता 'सुरक्षित भारत' है। उन्होंने कहा कि नौसेना ने भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है।

श्री मोदी ने तीन घण्टों तक नौसेना के सबसे बड़े और नवीनतम जहाज की नौसैनिक क्षमताओं को देखा, जिनमें रॉकेट फायरिंग डेमो, एयर पावर डेमो और नौसैनिक जहाजों द्वारा स्टील पास्ट जैसी घटनाएं शामिल थीं। इस जहाज की क्षमताओं के बारे में श्री नरेन्द्र मोदी को बताया गया। इससे पूर्व, प्रधानमंत्री का स्वागत चीफ आफ नेवल स्टाफ, एडमिरल आर.के. धवन ने आइएनएस हंसा नेवल बेस पर किया। आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद प्रथम बार यहां आया हूं और सीधा विक्रमादित्य पर पहुंचा हूं। नौसेना के ऐतिहासिक प्रसंग को उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में महासम्राट शिवाजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के समुद्री व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए नौसेना के कार्यों की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि तटवर्ती के साथ-साथ हरेक ब्लाक में नौसेना एनसीसी की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के छोटे देशों की सुरक्षा के लिए भारत में निर्मित हथियारों और उपकरणों का निर्माण होना चाहिए। ■

का काम उन्होंने पीएमओ से शुरू किया है।

देश बहुत आशा भरी निगाहों से नरेन्द्र मोदी और नई सरकार की ओर देख रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनडीए सरकार ने अपनी प्राथमिकता को जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए नरेन्द्र मोदी ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय रहा है।

यह बात तो सच है कि थोड़ा समय लगेगा पर भारत का भविष्य संवरने की दिशा में अब एक नहीं अनेक फैसले होंगे। ■

भूटान संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री का भाषण

भूटान और भारत की सांझी विरासत हमें जोड़ती है : नरेन्द्र मोदी

गत 16 जून 2014 को थिम्पु में भूटान संसद के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब-करीब पिछली एक शताब्दी सत्ता के विस्तार, सुशासन और विकास के लिए मतदान किया है।

भूटान की नेशनल असेम्बली के स्पीकर महामहिम श्री जिग्मे जांग्पो के भाषण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जितना सशक्त होगा, उतना ही भूटान को लाभ होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण क्षेत्र खासतौर से सार्क देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी सम्पन्न होना आवश्यक है। केवल एक मजबूत और

राजनीति के केंद्रीकरण जैसी गतिविधियों से भरी पड़ी रही, लेकिन भूटान अपवाद सिद्ध हुआ है। भूटान ने लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का प्रयास किया है। भूटान ने बहुत ही उत्तम तरीके से, लोकशिक्षा के माध्यम से जन-मन को धीरे-धीरे तैयार करते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए यहां लोकतंत्र की परंपराओं को प्रस्थापित किया है। यहां के लोकतंत्र की प्रक्रिया में यहां की संसद की गरिमा, यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रति सामान्य मानव की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यहां के मतदाताओं ने जो जागरुकता दिखाई है वह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए शुभ संकेत है। भारत में भी अभी-अभी चुनाव हुआ है और भारत की जनता ने

प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा

प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमालय राज्य भूटान की सर्वप्रथम यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय बंधनों के सहयोग और विस्तार पर अपनी सहमति प्रगट की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 15-16 जून 2014 की दो दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच अपने सम्बन्धों को और भी मजबूत करने पर बल दिया। भूटान आगमन पर थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए शाही भोज का आयोजन करते हुए कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के साथ गहरा योगदान देता है और यह आगे भी जारी रहेगा। दोनों देश एक-दूसरे के लिए बने हैं। हमारे पासपोर्टों के रंग भले ही अलग-अलग हों, परन्तु हमारी विरासत और मूल्य एक जैसे हैं। 16 जून को श्री मोदी ने भूटान की संयुक्त संसद में भाषण दिया। संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच संबंध ऐतिहासिक हैं। हमारी नई सरकार इन संबंधों को और भी मजबूत करेगी। इस क्षेत्र यहां के लोगों के लिए लोकतंत्र की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मजबूत भारत भूटान और अन्य सार्क देशों के लिए कहीं बेहतर साबित होगा।

समृद्ध भारत ही पड़ोसी के सामने आने वाली समस्या से उसे निजात दिला सकता है।

भारत-भूटान संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक संबंधों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान दोनों ने ही शासकीय परिवर्तन देखा है। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन संबंधों को कोई आंच नहीं आई। भारत में भी कई बार शासन व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन भारत और भूटान के संबंधों को कोई आंच नहीं आई है। भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं हैं। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण हैं। सांस्कृतिक परंपराओं और हमारे बंधनों के कारण हैं। हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखे हैं। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं। भूटान और भारत का नाता उस अर्थ में एक ऐतिहासिक धरोहर है और भारत और भूटान की आने वाली पीढ़ियों ने भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालना है, संजोए रखना है और उसको और अधिक ताकतवर बनाना है।

भूटान के विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी भी छोटे देश के लिए और इतनी कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए विकास एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भविष्य में विश्व के अनेक छोटे देश विकास के लिए भूटान की प्रगति के मॉडल को बारीकी से देखेंगे। दुनिया विकास दर की चर्चा कर रही है, जीडीपी की चर्चा कर रही है, तब भूटान हैपीनेस की चर्चा कर रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि शासक के दिल में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की कल्याण की भावना है।

श्री मोदी ने कहा कि भूटान की पनबिजली संभावनाओं को काम में लाने की योजनाएं केवल भूटान की अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी अथवा भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि भारत और भूटान का संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही मानवता के लिए योगदान करने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री ने भूटान के बजट में काफी राशि शिक्षा पर खर्च करने की चर्चा की और कहा कि इससे पता लगता है कि भूटान आज की पीढ़ी की समृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि के लिए भी बीज बो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इसमें योगदान करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत युवकों के फायदे के लिए भूटान में शिक्षा को आधुनिक टैक्नोलॉजी से जोड़कर ई-लाइब्रेरी का नेटवर्क स्थापित करने में मदद करेगा। इससे भूटान के युवक ज्ञान के भंडार के साथ जुड़े जाएंगे। दुनिया का जो भी ज्ञान होगा उन्हें इस टैक्नोलॉजी के माध्यम से हासिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत, भूटानी छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति को दोगुना कर देगा।

भारत और भूटान के संबंधों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इस बारे में श्री मोदी ने सुझाव दिया कि भारत के भूटान से लगे हिमालयी क्षेत्र और अगर चाहे तो नेपाल भी हर वर्ष एक खेल प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने से खुशहाली आती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को भी भूटान काम में ला सकता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई बार लोग कहते हैं कि हिमालय ने हम लोगों को अलग किया है, लेकिन उनका मानना है कि हिमालय ने हमें एकजुट किया है, क्योंकि वह हमारी साझा विरासत का एक अंग है। उन्होंने कहा कि हिमालय के दोनों तरफ के लोग इसे ताकत का स्रोत मानते हैं, लेकिन समय की मांग है कि हिमालय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए पहले ही एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार कर चुका है। उन्होंने कहा कि हिमालयी प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत हिमालय के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता है और भूटान को उससे काफी फायदा होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान पर्यटन की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण तैयार कर सकता है और एक सर्किट विकसित कर सकता है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य और भूटान शामिल हों। उन्होंने कहा कि ''आतंकवाद तोड़ता है, पर्यटन जोड़ता है''। श्री मोदी ने कहा कि अगर भूटान के प्राकृतिक संसाधन और संभावनाओं को मिला दिया जाए तो यह दुनिया के लिए एक बड़ा निमंत्रण होगा।

प्रधानमंत्री ने भूटान के तीसरे नरेश की टिप्पणी को उद्धृत किया : दूध और पानी की तरह, भारत और भूटान को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मित्रता अटूट है और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। उन्होंने अपने जोरदार स्वागत के लिए भूटान की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। नेशनल काउंसिल के चेयरमैन महामहिम डॉ. सोनम किंगा ने धन्यवाद भाषण किया। ■

भूटान में मोदी की यात्रा अत्यंत सफल : ट्शेरिंग टोबगे

भूटान के प्रधानमंत्री ट्शेरिंग टोबगे ने श्री नरेन्द्र मोदी की हाल की भूटान यात्रा को अत्यंत सफल बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ के पारम्परिक बंधनों को फिर से नई मजबूती मिलेगी। टोगबे ने संसद की संयुक्त सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एवं आपसी हितों के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम की पुनर्समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।■

संघर्ष विराम उल्लंघन का माकूल जवाब देने में सक्षम हैं हमारे सशस्त्र बल : जेटली

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने 14 व 15 जून को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान श्री जेटली ने पाकिस्तान की तरफ से संघर्षविराम के उल्लंघन पर पाक को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल एलओसी पर संघर्षविराम उल्लंघन का माकूल जवाब देने में सक्षम है।

श्री जेटली सेनाध्यक्ष जनरल श्री बिक्रम सिंह के साथ दो दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। रक्षा मंत्री का प्रभार संभालने के बाद जम्मू-कश्मीर का यह उनका पहला दौरा था। श्री जेटली के दौरे से एक दिन पहले पाकिस्तान की ओर से पुंछ और मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने राज्यपाल एनएन वोहरा व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भेंट कर राज्य के बाहरी व आतंरिक सुरक्षा परिदृश्य, अमरनाथ यात्रा और विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास कार्य समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

गौरतलब है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के सत्तासीन होने के बाद राज्य में किसी केंद्रीय मंत्री का यह पहला आधिकारिक दौरा था। श्री अरुण जेटली सुबह थलसेना प्रमुख जनरल श्री बिक्रम सिंह के साथ दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि श्री जेटली ने राजभवन में राज्यपाल श्री एनएन वोहरा से भेंट की। इससे पूर्व नेहरु गेस्ट हाउस में उमर अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे थे। श्री उमर ने श्री जेटली से सीधी मुलाकात में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए जंगबंदी के उल्लंघन से पैदा हुए हालात और रियासत में जारी आतंकरोधी अभियानों समेत पूरी रियासत के समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। करीब एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए किए प्रबंधों से लेकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर भी बातचीत हुई। ■

राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ मुख्य अंश

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 9 जून 2014 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 30 साल बाद किसी एक दल को बहुमत मिला है जो लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत है। अभिभाषण में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा रखा है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य महंगाई पर नियंत्रण पाना रहेगा। इसके साथ ही सरकार के एजेंडे में हर हाथ को काम देने का वादा भी प्रमुखता से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण और अल्पसंख्यकों को विकास और बराबरी का हिस्सा देने की बात भी की।

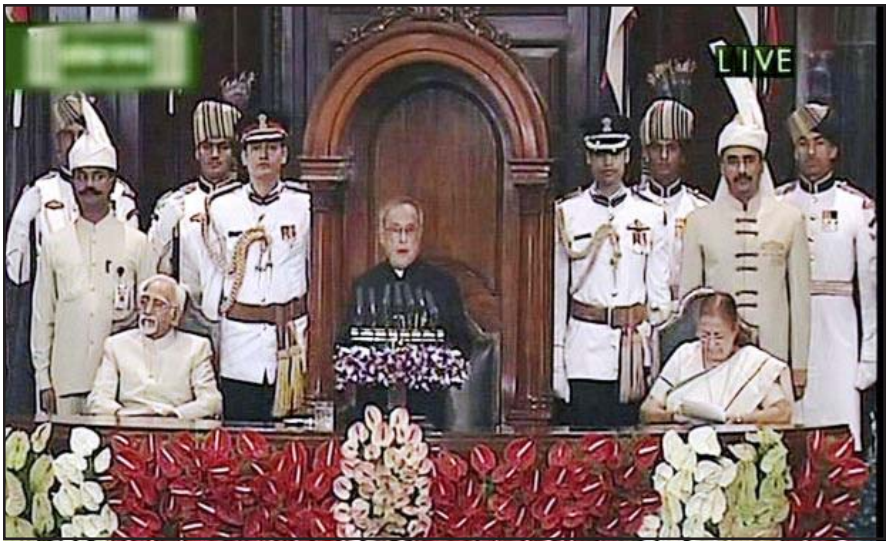

मोदी सरकार के एजेंडे में महंगाई दूर करने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। वहीं भ्रष्टाचार को देश में बर्दाश्त नहीं करने का दावा किया गया है। इसके अलावा सरकार के एजेंडे में किसानों का भी ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए नई सुविधाएं देने का वादा किया गया है। इसके अलावा देश में कालाबाजारी पर लगाम लगाने का दावा किया गया है।

अपने पहले अभिभाषण में चुने हुए सांसदों का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 30 साल बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है। राष्ट्रपति ने नई लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बहुमत लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं।

अभिभाषण की मुख्य बातें-

- रोजगार के लिए एफडीआई को बढ़ावा।
- भ्रष्टाचार रोकना सरकार की प्राथमिकता होगी।
- महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- कश्मीरी पंडितों के वापसी पर जोर रहेगा।
- अमेरिका से रिश्ता मजबूत होगा।
- सभी राज्यों में एम्स जैसा अस्पताल बनेगा।
- संसद में 33 फीसदी महिला आरक्षण।
- 2022 तक सबको घर, सबको बिजली मिलेगी।
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जरूरतें पूरी की जाएंगी।
- हर राज्य में IIT, IIM जैसे संस्थान बनेंगे।
- नई स्वास्थ्य योजना और नई बीमा नीति पर काम किया जाएगा।
- कृषि उत्पादों के मूल्य और भंडारण पर जोर रहेगा।
- हर घर में शौचालय की नीति बनेगी।
- पूर्वोत्तर में रेल के विकास पर जोर दिया जाएगा।
- देशभर के मदरसों का आधुनिकीकरण होगा।
- पूर्वोत्तर में घुसपैठ से निपटेंगे।
- टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाएंगे।
- जापान से तकनीकी सहयोग को बढ़ावा।
- 2015 में मनाया जाएगा प्रवासी दिवस।
- वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे।
- नेशन वॉर मेमोरियल से शहीदों को सम्मान देंगे।
- बिजली उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा।
- ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर जोर रहेगा।
- नेशनल मिशन ऑफ हिमालय शुरू करेंगे।
- तटीय सुरक्षा के लिए नेशनल मैरिटाइम अथॉरिटी।
- चीन के साथ सामरिक और रणनीतिक संबंध बनाने पर जोर। ■

हम सबके साथ और सबके विकास में विश्वास करते हैं

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा:

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सभी दलों के नेताओं ने अपने- अपने विचार रखे हैं। कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए हैं, कुछ एक में अपेक्षाएं भी व्यक्त की गई हैं। उन सुझावों का आने वाले दिनों में रचनात्मक तरीके से सही उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे। कई वर्षों के बाद देश ने एक ऐसा जनादेश दिया है, जिसमें स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है और एक स्थिर सरकार के लिए वोट दिया गया है। हमारे मतदाताओं की संख्या अमेरिका और यूरोप के मतदाताओं की कुल जनसंख्या से ज्यादा है, यानी हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। हम सबका सामूहिक कर्तव्य है कि हम भारत की इस लोकतांत्रिक ताकत को विश्व के सामने उजागर करें। विजय और पराजय दोनों में सीख देने की ताकत होती है। जो विजय से सीख नहीं लेता है, वह पराजय के बीज बोता है और जो पराजय से सीख नहीं लेता, वह विनाश के बीज बोता है।

भारत की ताकत उसका संघीय ढाँचा है। अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो राज्यों को आगे बढ़ना होगा, अगर राष्ट्र को समृद्ध होना है, तो राज्यों को समृद्ध होना होगा और अगर राष्ट्र को सशक्त होना है, तो राज्यों को सशक्त होना पड़ेगा। आज एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनने का अवसर मिला है, जो राज्यों की पीड़ा को भली- भाँति समझता है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम कार्य करेंगे। हमें राज्यों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा।

हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया है कि यदि हमें भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश को चलाना है तो प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों को एक 'टीम इंडिया' के रूप में काम करना पड़ेगा। कुछ लोग 'गुजरात मॉडल' के बारे में जानना चाहते हैं। मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने अपने यहां कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे समझना, स्वीकार करना और हमारे यहां लागू करना यह 'गुजरात मॉडल' है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम एक मॉडल की चर्चा कर रहे हैं और वह भी विकास के संदर्भ में। मैं यह सुनने को लालायित हूँ कि राज्य विकास के संदर्भ में दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करें और उन्हें पीछे छोड़ने का प्रयास करें। हम अपने देश को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं।

हमारे देश में प्रत्येक राज्य की अपनी शक्तियाँ और कठिनाइयाँ हैं। हमें इसे समझना होगा। गुजरात एक छोटा राज्य है परंतु एक ही मॉडल को इसके सभी जिलों में लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक राज्य के मॉडल को अन्य राज्यों पर नहीं थोपा जा सकता। हमें उस राज्य की प्राथमिकताओं और कठिनाइयों को समझना होगा। विकास राज्य और देश दोनों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। हमें देश के सभी राज्यों को मजबूत बनाना होगा। हम भारत के पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर के बराबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम सबके साथ और सबके विकास में विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि विकास सर्वसमावेशी और सर्वहितकारी होना चाहिए।

हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को केवल आर्थिक मदद देते हैं और बाकी सब उसके नसीब पर छोड़ देते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? देश में 30,000 से अधिक कॉलेज हैं। यदि हम प्रत्येक कॉलेज से 100 छात्रों को साल में एक बार सप्ताह या दस दिन के लिए पूर्वोत्तर के टूर पर भेजते हैं तो इससे न केवल वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वे लोग पूरे देश से खुद को जुड़ा हुआ भी महसूस करेंगे। हमें देश को चलाने के नए तरीके ढूंढने होंगे। हम हमेशा राष्ट्रीय एकता

और एक भारत की बात करते हैं। आज जातिवाद तथा प्रांतवाद ने देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। हमें एकता की भाषा बोलनी चाहिए, विभाजन की नहीं। हमारा सपना अपने देश को एक ऐसा श्रेष्ठ भारत बनाने का है जोकि सभी भाषाओं, जातियों और समुदायों से परे हो। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। हमें इसकी विविधता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी वजह से हम ''एक भारत-श्रेष्ठ भारत'' के सपने के साथ देश के कल्याण की बात करते हैं। देश में प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं और कठिनाइयाँ हैं। हम हिमालयन स्टेट्स को तराई के इलाकों के प्रगति के मॉडल में फिट नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने यह उल्लेख किया है कि हिमालयन रेंज के सभी राज्यों को साथ बैठना चाहिए और अपनी समस्याओं को समझते हुए एक कॉमन व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। हमने तटवर्ती राज्यों में समुद्र तट के विकास की बात भी की है। हमारा तटवर्ती क्षेत्र देश की समृद्धि का साधन बन सकता है। हमारे विचार से देश के सभी तटवर्ती राज्यों को एकसाथ बैठना चाहिए और समन्वित प्रयासों के साथ तटवर्ती विकास के बारे में वार्ता करनी चाहिए। अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण भारत पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली एक बड़ी सामुद्रिक ताकत बन सकता है। देश के कई क्षेत्र माओवाद से प्रभावित हैं। इस समस्या के समाधान हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।

राज्य आवश्यक रूप से नीति आधारित होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। आज प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रौद्योगिकी द्वारा इतनी पारदर्शिता आ सकती है कि एक आम आदमी भ्रष्टाचार करने से पहले 50 बार सोचेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी ई- निविदा वगैरह छोटी- मोटी चीजें प्रारंभ हुई हैं, लेकिन उसको और व्यापक रूप से आगे लाया जाए।

कृषि क्षेत्र में हमारे यहां एग्रो- क्लाइमेट जोन हैं। गेहूँ उपजाने वाले राज्यों की समस्याएं गन्ना या चावल उगाने वाले राज्य से अलग हैं। जब तक हम इश्यू - सेंट्रिक फोकस एक्टिविटी नहीं अपनाते हैं तब तक इस देश की स्थिति नहीं बदलेगी। अपने विचारों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना आज के समय की मांग है। अपने- अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्येक सरकार ने कुछ न कुछ किया है। लेकिन यह पर्याप्त और सही दिशा में नहीं था। हमारे लोकतंत्र में हमने सुशासन पर बल नहीं दिया है। सुशासन सामान्य नागरिक के प्रति जवाबदेह होता है परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है। आज समय की मांग है कि हमें देश में स्वराज पर बल देना चाहिए। जिस तरह से डायबिटीज पूरे शरीर को नष्ट कर देती है उसी प्रकार कुशासन पूरे शासन- तंत्र तथा पूरे देश को नष्ट कर देता है।

भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी चिंता है और इसने पूरे विश्व के सामने भारत की छवि को 'रकैम इंडिया' के रूप में प्रस्तुत किया है। बलात्कार की घटनाओं ने हमारे पर्यटन को प्रभावित किया है। हमें आतंकवाद, माओवाद तथा बलात्कार के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें मिल - बैठकर इन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए ताकि हमारे देश की छवि अच्छी हो सके। यह सभा विद्वत् सभा है जो देश के टैलेंट का प्रतिनिधित्व करती है। देश का मार्गदर्शन करना होगा। हमें मिलकर देश के विकास के तरीके खोजने होंगे।

राज्य आवश्यक रूप से नीति आधारित होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। आज प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रौद्योगिकी द्वारा इतनी पारदर्शिता आ सकती है कि एक आम आदमी भ्रष्टाचार करने से पहले 50 बार सोचेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी ई- निविदा वगैरह छोटी- मोटी चीजें प्रारंभ हुई हैं, लेकिन उसको और व्यापक रूप से आगे लाया जाए। बायोमिट्रिक सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और भ्रष्टाचारी लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था हो, तो मुझे विश्वास है कि हम स्थितियों को बदल सकते हैं। हमारे इन सदनों की गरिमा गिरी है। यह हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इन दोनों सदनों की गरिमा बहाल करें। भारत के उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करें कि सदस्यों के विरुद्ध मामलों में एक साल के भीतर न्याय होना चाहिए। 2015 में हम एक शुरुआत कर सकते हैं। जब एक बार सर्वसम्मति से माहौल बन जाएगा तो हम राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कर सकते हैं।

कानून का राज होना चाहिए। बेगुनाहों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। हमने सत्ता में आते ही काले धन पर विशेष जांच अभिकरण गठित कर दिया। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश के सामान्य व्यक्ति की संसद, लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और वह सरकारी

व्यवस्था में भरोसा करने लगेगा। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि उसका भरोसा टूट गया है। उसको पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी सुझाव हमारे लिए सम्मानीय हैं। हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमें सभी अच्छी बातों को आगे बढ़ाना है। राजनीति करने के लिए आखिरी वर्ष काफी होता है। अभी तो चार साल सिर्फ राष्ट्र हित और राष्ट्रनीति के लिए सोचें। मुझे विश्वास है कि देश के सपनों को पूरा करने के लिए जो दायित्व होता है, उस दायित्व को पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए देश को नई दिशा दें, नई ताकत दें। ■

हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का मान बढाएंगे : सुषमा स्वराज

श्री राजीव प्रताप रूडी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कल इस सदन में प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमने पूर्व में इस तरह के अभिभाषणों को अनेक बार सुना है, पढ़ा है और उस पर चर्चा भी की है लेकिन इस राष्ट्रपति अभिभाषण की आभा निराली है। यह निराला इसलिए है क्योंकि इस अभिभाषण के प्रथम पृष्ठ से ले कर अंतिम पृष्ठ तक हमने पहले की सरकार पर कोई आक्षेप नहीं किया है। बल्कि यह देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका निराकरण करने की हमारी क्या दृष्टि है, केवल उसका खुलासा किया है। यह अभिभाषण हमें मिले स्पष्ट जनादेश से शुरू होता है और इस जनादेश ने भारत की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिली और 336 सीटें हमें अपने सहयोगी दलों के साथ मिली। इस जीत के दो प्रमुख कारण थे।

पहला कारण था कि लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए जात-पांत की दीवारें ढह गईं, उम्मीदवार गौण हो गए और लोगों ने लाखों-लाख के अंतर से हम लोगों को जिताया।

लेकिन इस जीत के साथ हम जानते हैं कि जितनी बड़ी विजय होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं।

अभिभाषण में कहा गया कि यह उम्मीदों का चुनाव है और हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की, जिसके कारण इस देश में जनआक्रोश उमड़ा था। हमें ऐसे 10 कारण दिखाई दिये। हमें महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, किसानों की दुर्दशा, बंद कारोबार, मंद व्यापार, युवाओं की बेरोजगारी, महिलाओं से दुराचार, संस्थाओं से दुर्व्यवहार और सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार जैसे 10 कारण दिखाई दिए।

जहां तक महंगाई का संबंध है, हमने अभिभाषण में अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा और उसको खत्म करने के उपाय के रूप में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के प्रभावी कदम उठाने का जिक्र भी किया। जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है सरकार देश को भ्रष्टाचार और कालेधन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कृत संकल्प है। जहां तक घोटालों को दूर करने का संबंध है हमने अपना संकल्प दोहराया है कि हम साफ-सुथरा प्रशासन देंगे और प्रणाली को पारदर्शी बनायेंगे। किसानों की दुर्दशा के संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि हमारे किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं और हताशा के कारण आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो गए हैं। आज खेती लाभ का धंधा नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि कृषि को वापस लाभ का उद्यम बनायेंगे। जहां तक बंद कारोबार का संबंध है, देश ठप्प हो गया है। कुछ चल नहीं रहा है।

मुझे खुशी है कि जो तीन मंत्र हमारे प्रधान मंत्री जी ने रखे है स्किल, स्केल और स्पीड, उसके माध्यम से हम इस देश को खड़ा भी करेंगे, चलाएंगे भी और बहुत जल्दी दौड़ाएंगे भी। जहां तक मंद व्यापार का संबंध है हमने कहा है कि हम हालात बदलेंगे और हमारा व्यापार केवल भारत में ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में हम प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगे। जहां तक युवाओं की बेरोजगारी का संबंध है, हम एक मल्टी स्किल मिशन लागू करेंगे जिससे हम युवा प्रतिभाओं में तरह तरह के कौशल का विकास कर सकें और वे स्वरोजगारी होकर आत्मसम्मान से जिन्दगी जी सकें। महिला सशक्तिकरण के बारे में, मैंने बार-बार कहा है कि यदि हम महिलाओं का उत्थान चाहते हैं तो चार चीजें जरूरी है- शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनैतिक सशक्तीकरण। जहां तक 33 प्रतिशत आरक्षण का संबंध है, मैं चाहती हूं कि यह 16वीं लोक सभा मील का पत्थर विधेयक महिला आरक्षण को पारित करे।

जहां तक संस्थाओं से दुर्व्यवहार किए जाने का संबंध है, इन घटनाओं से देश की संघीय भावनाओं को कमजोर किया गया है। संघीय ढांचा इस देश के संविधान का मूल प्राण है। सीवीसी, सीएजी और सीबीआई लोकतंत्र के वह खम्भे हैं, जिन्हें निष्पक्षता से काम करने का अधिकार होना चाहिए। इनको लेकर संघ और राज्यों के बीच में टकराव इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।

इसलिए हमने कहा है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद जैसी परिषदें बनी हैं, हम इनका पुनर्गठन करेंगे और इनको एक सशक्त टीम इंडिया के रूप में खड़ा करेंगे। जहां तक सैनिकों के साथ अत्याचार किए जाने का संबंध है सरकार अपने सैनिकों के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएगी। एक रैंक, एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।

ये सभी वे दस बिंदु हैं जिनका जिक्र हमने इस अभिभाषण में किया है। ऐसा कहा गया है कि अभिभाषण में योजनाओं का जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में हमने कुछ बड़ी योजनाएं बतायी हैं। हमने कहा है कि हम हर राज्य को आईआईटी देंगे। हम हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण करेंगे। हम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सौ नये शहर बनाएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों जैसी योजना के तर्ज पर हम रेल का हीरक चतुर्भुज बनाएंगे, हम गंगा का पुनरुद्धार करेंगे, क्या ये बड़ी योजनाएं नहीं हैं? जहां तक हमारी विदेश नीति का संबंध है मैं कह सकती हूं कि हमारी सरकार के आने के बाद रातों-रात दुनियां में भारत का महत्व बढ़ गया है। भारत की संभावना वापस लौटी है। मैं कहना चाहती हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की नाक ऊंची करेंगे और यह हमारी कटिबद्धता है। ■

भारत अपना खोया हुआ गौरव हासिल करेगा : कीरेन रिजीजू

एक भारत और श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास इस बुलंद नारे के साथ इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू करने का निर्णय किया है। वे उन क्षेत्रों और उन लोगों के लिए एक नए दिन की शुरूआत है। हिन्दुस्तान के आदिवासी लोगों को तैयार करने का सरकार ने निर्णय किया है। मुझे लगता है कि ये जंगल की जमीन के नाम पर पीछे धकेले गए हैं, अब उनके लिए मुख्यधारा में आने की शुरूआत है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य परस्पर संपर्क का जिक्र हुआ है। हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण का संरक्षण बहुत सेंसेटिव सब्जेक्ट है। हिमालय क्षेत्र के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयाज की चर्चा दिनों से चल रही थी। 14वीं लोक सभा में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पार्लियामेंटरी फोरम भी बनाया था। हिन्दुस्तान की नदियों में फ्रेश पानी का 80 प्रतिशत जल हिमालय से बह कर आता है। जब हिमालय का संरक्षण नहीं होगा तो हिन्दुस्तान स्वस्थ भारत नहीं हो सकता। सरकार ने इस चीज को समझा है। इस सरकार ने 50 प्रतिशत सर्किट और पिलग्रिमेज टूरिज्म डेस्टिनेशन की एक रूपरेखा रखी है। इससे मुझे लगता है कि आज से पांच साल के बाद पर्यटकों की संख्या

बढ़कर तीन-चार गुणा हो जाएगी। हमारी विदेश नीति विस्तारवादी नहीं है। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। सीमा क्षेत्र के बारे में भूतपूर्व सरकार की जो निगेटिव पॉलिसी थी उसे बदलना है। चाइना के साथ हमारा बार्डर डीलिनिएशन नहीं हुआ। लेकिन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था, उसमें यह पाइंट है कि जब हम तय करेंगे कि हमारा बार्डर कहां है तो उस समय दोनों जगह में जो रहने वाले निवासी हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड इंडिया की जो बात की है, जिसमें हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग जब एक साथ हिन्दुस्तान के नाम पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो विश्व में हमारा खोया हुआ गौरव और सम्मान हमें इज्जत के साथ वापिस मिलेगा क्योंकि भारत स्वभाविक रूप से विश्व का नेतृत्वकर्ता है। ■

हमारी सरकार व्यवस्था की खामियों को दूर करना चाहती है : राजीव प्रताप रूडी

आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब अगले पांच वर्षों तक इस सदन में बैठकर देश के निर्माण में काम करेंगे। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा है, हमने यहां से शुरूआत की है। हमने यह भी कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ है एक व्यक्ति के प्रयास से जो आज हमारे बीच सबसे पहली पंक्ति में बैठा है। यह वही व्यक्ति है, जिसने चुनावों में 125 करोड़ लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जो शायद दुनिया के इतिहास में किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में 282 की संख्या के साथ सत्ता में है।

आखिर यह जनादेश हमें क्यों मिला क्योंकि हमारे प्रति लोगों का विश्वास था। गरीब लोगों की आशा थी कि अब उन्हें दो वक्त की रोटी मिलेगी। नौजवानों को उम्मीद थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा। महिलाओं को आशा थी कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी तथा निम्न मध्यम वर्ग को आशा थी कि उन्हें महंगाई से निजात मिलेगी। इसलिए आज देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधान मंत्री और पूरे मंत्रिपरिषद पर है। इन चुनावों में लोगों द्वारा भाजपा को दिया गया जनादेश इनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया गया है। आजादी के 65 वर्षों के पश्चात् भी देश के लोग आधारभूत सेवाओं जैसे शौचालय सुविधा से वंचित हैं। शहरी महिला सुरक्षा चाहती है। लोअर मिडल क्लास की उम्मीद है कि हम महंगाई से लड़ सकें। मजदूर सही वेतन चाहते हैं। बिजनेसमैन चाहते हैं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई उन्हें टैक्स में तंग न करे और इन्हें ऐसा वातावरण मिले कि वे अपना उद्योग ठीक से चला सकें। अमीर आदमी सोचता है कि मैं और वेल्थ क्रिएट करूं और बढ़ सकें और इस देश के निर्माण में वेल्थ क्रिएट कर के सरकार को दे सकूं ताकि इस देश का निर्माण हो सके। पटना में अभी भी तीन संसदीय क्षेत्र हैं, जिनमें रहने वाले 50,000 लोगों के पास आज तक आजादी के 65 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं है। आज इस देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और पूरे कैबिनेट पर है, इसलिए हम विश्वास के साथ सदन में बैठे हैं। इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है। आज इस देश में लगभग 40 करोड़ लोगों के बीच में बिजली नहीं है और हम इसे लोकतंत्र में स्वीकार कर रहे हैं और बैठे हैं। दूसरी तरफ, अगर चीन की तुलना करें, तो चीन प्रत्येक वर्ष 1 लाख मेगावाट बिजली जोड़ता है और हम यहां अभी पांच वर्ष में 70 हजार मेगावाट की योजना बनाते हैं। यह हमारे

लिए चुनौती है, शायद इसमें सबकी सहमति होगी। इसलिए आज हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, एक लक्ष्य के तहत अगले दस वर्षों में हमें इस देश में बिजली का उत्पादन पूरा करना होगा, चाहे अपारंपरिक स्रोत से हो, हाइडल हो या कन्वेंशनल हो। इस देश की बिजली, जो इस विकास की नींव बन सकती है, उसे हमें पूरा करना होगा और यह सरकार का संकल्प है।

इस देश में प्रत्येक माह दस लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम उदाहरण लें कि चीन ने गरीबी कैसे भगायी। उसने यह तय किया कि फॉर्म सैक्टर है, उसमें से लगभग 40 करोड़ लोगों को नॉन फॉर्म सैक्टर में पहुंचाया। लेकिन भारत की स्थिति अनूठी है कि 12 करोड़ लोग सामान्य जीवन से वापस कृषि क्षेत्र में जाने की स्थिति में हैं और यह यूपीए सरकार की देन है। दुनिया भर में देख गया है कि जहां लोग, अगर विकास और गरीबी से लड़ना हो, तो फॉर्म सैक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सैक्टर में जाते हैं, लेकिन पिछले दस वर्षों में भारत की ऐसी स्थिति हो गयी है कि 12 करोड़ लोग इंडस्ट्रियल सैक्टर से निकल कर फॉर्म सैक्टर में जाने के लिए तैयार हैं। हर सांसद से लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि उनके तथा उनके परिचितों के लिए रोजगार प्रदान करा दिए जाएं परंतु स्थिति यह है कि इस देश के उद्योगपति जो इस देश में निवेश करके यहां उद्योग लगा सकते हैं, वैसे उद्योगपतियों ने पिछले चार-पांच साल में अमेरिका में लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पिछले 65 वर्ष में हम एक भी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। आज देश के 45 प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और 21 प्रतिशत एमबीए ग्रेजुएट्स इम्प्लायबल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ सोचना होगा। आज लगभग दस करोड़ लोग पानी के अभाव में हैं। आज इस देश में 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको पानी लेने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इरीगेशन के लिए पानी का अभाव है। हम सबको मिलकर सोचना है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी समस्या का निदान करें।

वे यहां से छोड़कर चले गये हैं और अमेरिका में रोजगार सृजित किया है। अत: भारत का एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक हो।

पिछले 65 वर्ष में हम एक भी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। आज देश के 45 प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और 21 प्रतिशत एमबीए ग्रेजुएट्स इम्प्लायबल नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ सोचना होगा। आज लगभग दस करोड़ लोग पानी के अभाव में हैं। आज इस देश में 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको पानी लेने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इरीगेशन के लिए पानी का अभाव है। हम सबको मिलकर सोचना है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी समस्या का निदान करें।

देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के शपथ-ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के प्रमुख सहित दस देशों के प्रमुख उसमें आए और उस सौहार्दपूर्ण भेंट के सकारात्मक परिणाम हमें जल्द ही देखने में आए। जब जेस्चर के तौर पर श्रीलंका ने हमारे मछुआरों और नौकाओं को छोड़ने की घोषणा की। साथ ही चीन के प्रधानमंत्री से चल रही अनौपचारिक चर्चा 45 मिनट तक चली। जहां तक खेलों का संबंध है हमारी उपलब्धियां काफी कम रही हैं। हमारा 120 करोड़ की आबादी वाला देश एक गोल्ड, एक सिल्वर और कुछ मैडल ही ले पाता है। इसलिए सरकार ने देहातों से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए नेशनल टेलेंट सर्च योजना बनाई, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारकर उन्हें दुनिया के पटल पर रखा जाएगा।

जहां तक रेलवे की बात है, ब्रिटिश शासन के दौरान छोड़ी गयी लाइनों की दूरी में थोड़े बहुत विस्तार के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय उपलब्धि पिछले 65वें वर्षों में हमने प्राप्त नहीं की है। हमारी सरकार का इस बारे में एक स्पष्ट विजन है। हम रेल कॉरिडार, फ्रेट कॉरिडार की और स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। देश में ब्यूरोक्रेसी ने यह कहना शुरू कर दिया, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के पास कोई फाइल जाती है तो वह कहता है कि जरा हाई-कोर्ट से आदेश ले आइये, फिर हम अपनी संचयिका को क्लीयर कर देंगे, इस देश की यह स्थिति हो गयी है कि हर निर्णय के लिए न्यायालय को प्रवेश करना पड़ रहा है।

लंबे समय से चल रहे कुशासन के कारण विभिन्न पदाधिकारियों और राजनेताओं की भूमिका ही बदल गयी है और एक भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था अनेक खामियों से ग्रस्त है। हमारी सरकार इस स्थिति में परिवर्तन करना चाहती है। ■

विकास प्रक्रिया में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाना होगा : अरुण जेटली

राष्ट्रपति का अभिभाषण अगले कई वर्षों के लिए वर्तमान एनडीए सरकार की भावी योजना को दर्शाता है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत एक जीवंत सफल लोकतंत्र है जिसमें निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हैं तथा एक सरकार से दूसरी सरकार को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है। परंतु लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि जीतने वाले को कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी सदा के लिए शासन नहीं करने वाला है और लोगों के स्थान बदलते रहते हैं। इन परिणामों का और भी गहरा अर्थ यह निकलता है कि तीन दशकों के बाद हमारी लोक सभा ऐसी है जहां जनता ने एक दल को बहुमत के साथ चुना है। मेरे दल का विश्वास है कि बहुमत के साथ जीतने के बावजूद हम गठबंधन के युग में हैं क्योंकि गठबंधन भारत के संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। यदि देश पर ठीक प्रकार से शासन नहीं किया जाए तो केवल जाति ही किसी दल को नहीं बचा सकती। लोग शासन चाहते हैं और केवल संयोजन या सामाजिक संयोजन शासन का स्थान नहीं ले सकते। जो परिवारवाद की राजनीति में विश्वास करते थे उन्हें इस चुनाव में गहरा धक्का लगा है। वोट बैंक की राजनीति तथा जाति आधारित राजनीति की हार दर्शाती है कि भारतीय लोकतंत्र विकसित हो रहा है। लोग राजनीतिक अस्थिरता नहीं चाहते। हमारे दल को हमारे विरोधियों पर जीत प्राप्त हुई क्योंकि लोग सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध थे और उन्होंने हम में तथा हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया। हमारी सरकार पर बहुत अधिक भार होगा क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं कि हम काम करके दिखाएं। यदि सरकार वह करती है जो किया जाना चाहिए तो लोग संतुष्ट होंगे। हमें पांच प्रतिशत से कम की विकास दर विरासत में प्राप्त हुई है। आपने देश को कम विकास दर, ऊँची मुद्रास्फीति, अत्यधिक वित्तीय घाटे, बहुत कम कर संग्रहण पर छोड़ा है। पूर्व शासन में बाहर से निवेश भारत में नहीं आ रहा था और निवेशक बाहर जा रहे थे। वर्तमान सरकार के पास सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए धन नहीं है। दोनों सभाओं तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जनता के विश्वास के वास्तविक संग्राहक हैं। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद सबसे अधिक जिम्मेदारी का होता है। सरकार से बाहर की शक्ति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री से बड़ी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को कोयला ब्लॉक आबंटन में भाई- भतीजावाद तथा कराधान नीति में अस्थिरता को नहीं आने देना चाहिए था।

लोग शासन चाहते हैं और केवल संयोजन या सामाजिक संयोजन शासन का स्थान नहीं ले सकते। जो परिवारवाद की राजनीति में विश्वास करते थे उन्हें इस चुनाव में गहरा धक्का लगा है। वोट बैंक की राजनीति तथा जाति आधारित राजनीति की हार दर्शाती है कि भारतीय लोकतंत्र विकसित हो रहा है। लोग राजनीतिक अस्थिरता नहीं चाहते। हमारे दल को हमारे विरोधियों पर जीत प्राप्त हुई क्योंकि लोग सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध थे और उन्होंने हम में तथा हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया। हमारी सरकार पर बहुत अधिक भार होगा क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं कि हम काम करके दिखाएं। यदि सरकार वह करती है जो किया जाना चाहिए तो लोग संतुष्ट होंगे।

किसी भी सरकार को देश को आगे ले जाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति बनानी होती है। सरकार को मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करना चाहिए और प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होना चाहिए। पूर्व सरकार कई वर्ष बिताने के पश्चात् कमजोर लोकपाल लाई। सरकार ने ऐसे नियम बनाए जो लोकपाल अधिनियम के विरुद्ध जाते हैं। संसद द्वारा अधिनियमित कानून पूर्ण रूप से प्रभावी होना चाहिए।

हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। व्यय में पूर्वोत्तर तथा जनजातीय क्षेत्रों को वरीयता देनी होगी जहां धन खर्च नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को

पुन:जीवित करना होगा और उत्पादन क्षेत्र में कम वृद्धि दर चिंता का विषय है। हमारा अधिकतर रेलवे वहीं है जो ब्रिटिश छोड़ गए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की शुरुआत से पिछले दो वर्षो में निम्नतम निष्पादन रहा है। चिंता के अन्य विषय हैं ग्रामीण अवसंरचना, बंदरगाह तथा विमानपत्तन। कुछ कार्यक्रमों की अतिव्याप्ति हो सकती है और कुछ में कटौती करनी पड़ सकती है। यदि भारत को सहकारी संघवाद की ओर बढ़ना है तो विकास प्रक्रिया में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाना होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में भी राज्यों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना होगा।

हमारा अधिकांश समाज प्रसन्न होगा यदि हम अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों का समाधान कर सके। सरकार विद्रोह, आतंकवाद अथवा माओवाद से संबंधित विषयों को शीर्ष वरीयता देगी।

हमारे पड़ोसियों के संबंध में सरकार की नीति हमारे सुरक्षा कारणों से अभिप्रेरित है। यदि सरकार राष्ट्रपति अभिभाषण में उल्लिखित बातों पर राष्ट्रीय सहमति बना सके तो यह देश के व्यापक हित में होगा। ■

देश में सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बना है : मुख्तार अब्बास नकवी

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए : -

''राष्ट्रपति ने 9 जून, 2014 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।''

देश ने सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। इस लोक सभा के चुनाव देश में अब तक हुए चुनावों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा, 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों, ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के हर कोने में लोकतंत्र के लिए एक जुनून था। इस चुनाव में लोगों के पास 'नोटा' का इस्तेमाल करने का एक विकल्प था, ताकि अगर किसी को कोई भी उम्मीदवार पसन्द नहीं हो तो वह नोटा का बटन दबा कर यह कह सकता है कि वह किसी को चुनना नहीं चाहता। लेकिन, लोगों ने ऐसा नहीं किया। देश के हर कोने में जो जुनून था, वह नकारात्मक नहीं था, वह सकारात्मक था। देश में जो चुनौतियां हैं, उनको हम सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से हल करना चाहते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि हमें एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था मिली, हमें महंगाई से पूरी तरह से बेहाल देश मिला, हमें बेरोजगारी से बेहाल नौजवान मिला, हमें देश में माफिया राज, अराजकता, नक्सलवाद और आतंकवाद का चौतरफा माहौल मिला क्योंकि हम सकारात्मक बात करना चाहते हैं। आज श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के प्रति एक सकारात्मक माहौल खड़ा किया है। हम आपके सहयोग से और देश के आशीर्वाद से घर को सुधारेंगे। देश ने जो हमें जनादेश दिया है वह माहौल को ठीक करने के लिए दिया है।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में 'सार्क' देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। उन्होंने एक सकारात्मक शुरुआत की। इसका असर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में दिखाई दिया जो भारत के प्रति और भारत के माहौल के प्रति कई तरह के सवालिया निशान रखते थे। देश का माहौल अच्छा हो, इसके लिए यह निश्चित तौर पर जरूरी है कि आस- पड़ोस में शांति और सद्भाव का माहौल हो। देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। चुनाव के फैसले ने जो संदेश दिया, वह सकारात्मक संदेश है, वह देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का संदेश है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने इसके लिए इच्छाशक्ति दर्शाई है।

अल्पसंख्यकों, पिछड़े तबके के लोगों, दलित तबके के लोगों, कमजोर तबके के लोगों के विकास का संकल्प इस सरकार ने लिया है। शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की सभी को जरूरत है। हम सबको समान अधिकार देने के पक्ष में हैं। देश का संघीय ढांचा देश के लोकतंत्र की और देश के संविधान की जान है।

हम देश के संघीय ढांचे को मजबूत, सकारात्मक और रचनात्मक रास्ते पर ले जाएं, इस बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हमारा संकल्प है कि देश सुरक्षित हो और देश के लोग सुरक्षित हों। देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, माओवाद खत्म होना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। ऐसी ताकतें जो आतंक पैदा करती हैं, उनमें खौफ होना चाहिए। हम आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद को मजहब, धर्म और जाति के नाम पर न देखना चाहते हैं और न उसे समझना चाहते हैं। इस देश के सामने जो भी सवाल खड़े हुए हैं, उनके समाधान का ईमानदार संकल्प लेकर यह सरकार काम करना चाहती है।

हम भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करेंगे : जगत प्रकाश नड्डा

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारत की जनता ने समुदाय से, जाति से, क्षेत्र से, मजहब से ऊपर उठ करके अपना जनादेश दिया है, जो भारत की राजनीति के लिए, भारत के प्रजातंत्र के लिए एक सकारात्मक दौर है। 1988 के बाद, लगभग 30 वर्ष के अंतराल के पश्चात, किसी एक राजनैतिक दल को इतना बड़ा जन – समर्थन मिला है। हमें जिस उद्देश्य के लिए यह जन– समर्थन मिला है। यह सकारात्मक जनादेश है। यह जनादेश लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है, यह जनादेश विकास के लिए है, यह जनादेश प्रभावी और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए है, वास्तव में यह जनादेश सुशासन के माध्यम से विकास के लिए है। यह जनादेश भ्रष्टाचार के संकट का मुकाबला करने के लिए है।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' से तात्पर्य है, हम विकास में सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। हम स्वार्थी नहीं हैं। हम नई नीतियों को नये तरीके से लागू करने के उद्देश्य से लाएंगे जो देश में परिवर्तन लाएगी। यह सरकार गरीबों के प्रति वचनबद्ध है। हम गरीबी को समूल समाप्त कर देंगे। सरकार महंगाई के प्रति गंभीर है और वह कृषि उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि करेगी। हम कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। यह सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

भारत गांवों में बसता है। जब तक हम गांवों की तस्वीर नहीं बदलेंगे तब तक हम देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। हम पंचायती राज संस्था को मजबूत करके गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि ग्रामीण जीवन शैली की आत्मा बची रहे और गांवों में लोग सारी शहरी सुविधाओं को उपयोग कर सके। हम सभी जानते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। हम कृषि के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम कृषि को फायदे का व्यवसाय बनाना चाहते हैं। पशु – पालन की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अच्छी प्रतिबद्धता है।

स्वास्थ्य देखभाल का सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से, हमने एक समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति और गरीब की पहुंच में हो। हम एक नई स्वास्थ्य नीति बनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए प्रत्येक राज्य में चरणबद्ध तरीके से 'एम्स' जैसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे। भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। हम युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यह युवा विकास से युवा संचालित विकास की ओर जाने वाली अवस्था है। हम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसको ऑन लाइन करेंगे। नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी। हम

प्रत्येक राज्य में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करेंगे। शिक्षकों और विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ई- पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। सरकार औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। 'हुनरमंद भारत' के लक्ष्य से एक राष्ट्रीय बहुकौशल मिशन शुरू किया जाएगा। हम शैक्षणिक रूप से आधुनिक मदरसे खोलने का प्रयास करेंगे।

शिक्षा की कमी और संपर्क मार्गों का अभाव आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के प्रमुख कारण हैं। इसलिए सरकार एक समर्पित 'वन बंधु कल्याण योजना' आरंभ करेंगी जिसके अंतर्गत आदिवासी बस्तियों के शत- प्रतिशत विद्युतीकरण और उनका बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपर्क का कार्य किया जाएगा। सरकार संसद और राज्यीय विधान मंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी एक व्यापक 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना देश के निरंतर विकास के लिए है। महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले में सरकार बिल्कुल सहनशील न रहने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का संघीय ढांचा कमजोर हो गया है। हम भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करेंगे। हम देश के विकास के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध वचनबद्ध है। एसआईटी के माध्यम से काले धन को वापस लाया जाएगा। हम भारत को एक विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के रूप में देखते हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। घरेलू उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि विकास का पर्यावरण से कुछ लेना- देना नहीं है। परंतु हम कहते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। हम दिखाएंगे कि ऐसा हो सकता है। हमारे पास समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत है जिसको मजबूत किए जाने की आश्यकता है। हम परंपरा, प्रतिभा, पर्यटन, व्यापार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को एक ब्रांड के रूप में विकसित करेंगे। ■

रेल किराया बढ़ने के पीछे की सच्चाई : अरुण जेटली

भारतीय रेलवे पिछले कुछ वर्षो से घाटे में चल रही है। रेलवे को बचाने का एकमात्र तरीका है जब यात्री रेल में मिलने वाली सुविधाओं के लिए भाड़ा दें। अब तक मालभाड़े से हो रही आमदनी से यात्री सेवाओं को चलाया जा रहा था। लेकिन हाल के वर्षो में मालभाड़े पर भी असर पड़ने लगा था।

जब यूपीए सत्ता में थी, उस वक्त 5 फरवरी 2014 को रेलवे बोर्ड ने मालभाड़े में 5 प्रतिशत और यात्री किराये में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव किया गया था कि मालभाड़ा 1 अप्रैल 2014 से और यात्री किराया 1 मई 2014 से लागू किया जाए। यहां तक कि रेलवे का अंतरिम बजट आना बाकी था, लेकिन इसके बावजूद इस उम्मीद में 1 मई 2014 की तारीख तय की गई कि तब तक आम चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे। रेलवे ने प्रस्ताव किया था कि इस बढ़ोतरी से रेलवे को 7900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। इस फैसले के साथ, तत्कालीन रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से 11 फरवरी 2014 को मुलाकात की। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी और सुझाव दिया कि मालभाड़े और यात्री किराये में बढ़ोतरी 1 मई 2014 से प्रभावी होनी चाहिए।

फलस्वरुप रेलवे बोर्ड ने इस बढ़ोतरी को 16 मई 2014 को अधिसूचित कर दिया जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। यह फैसला रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री की सहमति से लागू होना था। लेकिन रेल मंत्री घबरा गए और 16 मई 2014 की शाम को जब चुनावों में यूपीए के पराजित होने की घोषणा हुई, उन्होंने रेलवे बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया ताकि सैद्धांतिक रुप से उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले को एनडीए सरकार का रेल मंत्री लागू करे।

रद्द किए गए आदेश को वापस लेकर, वर्तमान रेल मंत्री, डी. एस. सदानंद गौड़ा ने चुनौती भरा फैसला किया है। श्री गौड़ा के सामने दो ही विकल्प थे कि या तो रेलवे को उसके हाल पर छोड़ दें और यूपीए सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए कर्ज के जाल में फंसते जाएं अथवा यात्री किराये और मालभाड़े में बढ़ोतरी करने संबंधी यूपीए सरकार के फैसले को लागू करें जिसे लागू करने का वह साहस नहीं जुटा पाई। घाटे में चल रही रेलवे से घटिया सेवाएं मिलेंगी। रेलवे के पास अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संसाधन भी नहीं हैं। भारत को यह तय करना होगा कि उसे विश्व स्तर की रेलवे चाहिए अथवा जर्जर रेलवे। रेल मंत्री ने कठिन लेकिन सही फैसला किया है। ■

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड एवं जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों पर विशेष

भाजपा को अच्छी सफलता प्राप्त होगी : रामलाल

लोकसभा चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे मनोयोग से और पूरी मेहनत से चुनावों में कार्य किया है। निश्चित रूप से इस जीत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनमें जनता का विश्वास और उसी कारण जनता का स्नेह और समर्थन, पार्टी कार्यकर्ताओं का परिश्रम तथा व्यवस्थित चुनाव संचालन है। इस ऐतिहासिक जीत के पश्चात प्रधानमंत्री के रूप में सांसदों द्वारा नेता चुने जाने के बाद संसद भवन में प्रवेश करते समय उसकी सीढ़ियों पर मत्था टेकना, नेता चयन के समय ओजपूर्ण व भावुकतापूर्ण उनका भाषण, शपथ ग्रहण में भी सांगठनिक, राजनीतिक व कूटनीतिक, तीनों निपुणता का परिचय देते हुए दक्षेस देशों के नेताओं को आमंत्रित करना और उसके पश्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के समय उनका भाषण और लोकसभा में सभी दलों के नेताओं से सहज मिलना आदि बातों ने उनके नेतृत्व को अत्यंत अहम बना दिया है।

चुनावी भाषणों में कई प्रकार के नारे प्रकाश में आए जैसे- ''सबका साथ-सबका विकास'' तथा ''एक भारत-श्रेष्ठ भारत'', इनका जनता के मन पर एक व्यापक असर हुआ। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उन बातों को स्मरण रखना, दोहराना ये अपनी बातों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है।

लोकसभा चुनावों में देशभर के सभी प्रांतों में तथा सभी वर्गों का एक व्यापक समर्थन मिला है। इसकी कल्पना भी कांग्रेस को नहीं रही होगी कि वो 14 राज्य और 6 केन्द्र शासित राज्यों में शून्य पर आ जाएगी तथा कई बड़े प्रदेशों में उसका नाममात्र का ही प्रतिनिधित्व रह जाएगा।

निश्चित रूप से पिछले वर्षों में केन्द्र में यूपीए का शासन था। उसकी नीतियों को और उसके नेताओं के आचरण को जनता ने नकारा है तथा भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में भी शासन में है वहां जिस ढंग से लोककल्याणकारी योजनाएं सामने लाई गईं तथा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित के कार्य हुए, विकास को लेकर में क्षेत्र, जाति, वर्ग एवं मजहब में कोई भेदभाव नहीं किया गया। इस सबका यह सम्मिलित परिणाम निकला कि जनता को भाजपा एक आशा की किरण दिखाई दी।

अभी चार राज्यों में चुनाव है। जहां तक इन 4 राज्यों का प्रश्न है, इन चारों राज्यों में

लोकसभा चुनावों में देशभर के सभी प्रांतों में तथा सभी वर्गों का एक व्यापक समर्थन मिला है। इसकी कल्पना भी कांग्रेस को नहीं रही होगी कि वो 14 राज्य और 6 केन्द्र शासित राज्यों में शून्य पर आ जाएगी तथा कई बड़े प्रदेशों में उसका नाममात्र का ही प्रतिनिधित्व रह जाएगा। निश्चित रूप से पिछले वर्षों में केन्द्र में यूपीए का शासन था। उसकी नीतियों को और उसके नेताओं के आचरण को जनता ने नकारा है तथा भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में भी शासन में है वहां जिस ढंग से लोककल्याणकारी योजनाएं सामने लाई गई तथा गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित के कार्य हुए, विकास में क्षेत्र, जाति, वर्ग एवं मजहब में कोई भेदभाव नहीं किया गया। इस सबका यह सम्मिलित परिणाम निकला कि जनता को भाजपा एक आशा की किरण दिखाई दी।

भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अभी तक की ऐतिहासिक विजय मिली है। कांग्रेस के अलावा इन राज्यों के कई क्षेत्रीय दल जिन्होंने भाजपा से दूरी बनाकर रखी है वो भी हाशिए पर चले गए हैं। और इसलिए हमें विश्वास है इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को अच्छी सफलता प्राप्त होगी।

आपने पूछा कि चारों राज्यों में पार्टी की तैयारी कैसी है? तीन राज्यों के प्रमुख नेताओं के साथ स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ जी की लंबी वार्ता हुई है। श्री गोपीनाथ मुण्डे जी के आकस्मिक निधन के कारण महाराष्ट्र की बैठक अभी कुछ समय पश्चात होगी। इस अर्थ में पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। चुनावों में विशेष रूप से अच्छे वातावरण को जीत में बदलने के लिए मुद्दों को जनता के समक्ष लाना, व्यवस्थित चुनाव संचालन व बूथ तक की सांगठनिक इकाई को सक्रिय एवं प्रभावी करना महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष जी के साथ बैठकों में इन सभी पहलूओं पर चर्चा हुई है। प्रदेश की ईकाईयों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक बड़ा काम वोटर लिस्ट के संशोधन का है। गलत नाम निकलें, सही नाम जो उसमें छूट रहे हैं वो जुड़ें इसके लिए चुनाव आयोग ने चारों राज्यों में जून महीने में विशेष योजना बनाई है। पार्टी के कार्यकर्ता इस दृष्टि से सचेष्ट रहते हुए वोटर लिस्ट संशोधन के काम में अच्छी भूमिका का निर्वाह करेंगे।

बूथ इकाइयां लोकसभा चुनाव के समय ही ठीक प्रकार बनी थीं। लोकसभा चुनावों के परिणामों में जहां जीत हुई है वहां भी समीक्षा करते हुए जिन बूथ पर कुछ विशेष करने योग्य विषय हैं, वो भी निश्चित समय सीमा में सभी इकाइयों को करने होंगे। शीघ्र ही चुनाव संचालन के लिए और अन्य विषय के लिए टोलियां भी प्रदेश इकाइयां बनाएं यह आग्रह किया गया है। यह बैठकें निश्चित रूप से उचित समय पर एक सार्थक पहल सिद्ध होंगी।

पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। चुनावों में विशेष रूप से अच्छे वातावरण को जीत में बदलने के लिए मुद्दों को जनता के समक्ष लाना, व्यवस्थित चुनाव संचालन व बूथ तक की सांगठनिक इकाई को सक्रिय एवं प्रभावी करना महत्वपूर्ण विषय है। अध्यक्ष जी के साथ बैठकों में इन सभी पहलूओं पर चर्चा हुई है। प्रदेश की ईकाईयों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक बड़ा काम वोटर लिस्ट के संशोधन का है। गलत नाम निकलें, सही नाम जो उसमें छूट रहे हैं वो जुड़ें इसके लिए चुनाव आयोग ने चारों राज्यों में जून महीने में विशेष योजना बनाई है। पार्टी के कार्यकर्ता इस दृष्टि से सचेष्ट रहते हुए वोटर लिस्ट संशोधन के काम में अच्छी भूमिका का निर्वाह करें।

जहां तक एक-एक प्रांत का प्रश्न है, जम्मू-कश्मीर में लेह-लद्दाख सहित, जम्मू, उधमपुर-तीन सीटें जीतने के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। कश्मीर घाटी में भी हमारे मत बढ़े हैं।

हरियाणा का जहां तक प्रश्न है वहां भाजपा आठ सीटों में से सात सीटें जीती है। वहीं मुख्यमंत्री की गृह सीट रोहतक पर भाजपा के प्रत्याशी को 3 लाख से अधिक वोट मिला है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। हरियाणा की जनता केन्द्र के कुशासन से त्रस्त थी। जिस तरह हरियाणा में भी पिछले पांच सालों में जो कुशासन चला है तथा अनेक प्रकार के घोटाले विशेष रूप से जमीन घोटाले उभर कर के आए हैं, निश्चित रूप से सरकार में भागीदार जनप्रतिनिधियों को वहां की जनता इस लूट की अब और अनुमति नहीं देगी। अब जनता भाजपा को एक विकल्प के रूप में देख रही है। यही स्थिति महाराष्ट्र की भी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की छवि भ्रष्टाचार, घोटाले और लूट की हो गई है। वहां भी भाजपा का गठबंधन निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा।

जहां तक झारखण्ड का प्रश्न है पिछले 14 वर्षों में कई सरकारें बनी हैं। लेकिन किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे देश की जनता ने केन्द्र सरकार के लिए पूर्ण बहुमत देकर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है तथा स्पष्ट जनादेश दिया है, झारखण्ड में भी 14 साल की परम्पराओं से हटकर भाजपा के पक्ष में पूर्ण बहुमत का स्पष्ट जनादेश जनता देगी। दोनों जगह एक ही दल की सरकार होने से नीतियां, कार्यक्रम और उनके कियान्वयन में एकरूपता के कारण केन्द्र के साथ चारों राज्य भी विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर होंगे। ■

(भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री राम लाल के साथ कमल संदेश के कार्यकारी संपादक डॉ. शिवशक्ति बक्सी की बातचीत पर आधारित।)

अराजकता का ठिकाना

✍ बलबीर पुंज

पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित 'निवेश सम्मेलन' से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रदेश में तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार के साथ 54,056 करोड़ रुपये के 19 एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली अधिकांश कंपनियां वही हैं जो पहले से किसी न किसी रूप से प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इस 'निवेश सम्मेलन' से गद्‌गद् होने वाले मुख्यमंत्री को इसकी चिंता होनी चाहिए कि आखिर नए निवेशक प्रदेश में निवेश करने से क्यों घबरा रहे हैं? जो उद्योग-धंधे प्रदेश में हैं वे बंदी की कगार पर क्यों हैं और निवेशक पलायन करने को क्यों मजबूर हैं? एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुनरमंद भारत का रोडमैप देश के सामने रख रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खोखले दावों के आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश हुनरमंद नहीं होगा, देश हुनरमंद नहीं होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की जगह अराजकता का साम्राज्य हो, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हों, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्य को उत्तम प्रदेश बताने का दावा करे?

मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव अपने 27 महीने के कार्यकाल में कोई छाप क्यों नहीं छोड़ पाए? क्यों उनकी सरकार का इकबाल शून्य पर है? क्या उनकी सरकार का सारा ध्यान तबादला, बहाली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीनें आवंटित करने आदि पर केंद्रित नहीं है? राज्य में बिजली का गहन संकट है, विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र ठप हैं या अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश में 12,700 मेगावाट प्रतिदिन बिजली की जरूरत है, सरकार केवल 10,700 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध करा पा रही है। बिजली चोरी और लीकेज के कारण सरकार को सालाना 7000 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है। सड़कें टूटी-फूटी हैं या नदारद हैं। समझ में नहीं आता कि सड़कों में गढ्‌ढे हैं या गड्‌ढों में सड़क है। गर्मी के मौसम में लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। परिवारवाद ने सरकारी महकमों के हाथ बांध रखे हैं, किंतु सरकार उपलब्धियां गिनाती नहीं थकती। विकास कागजों में दिखता है और उसी की परिणति है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने सपा को सिरे से नकार दिया।

मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव अपने 27 महीने के कार्यकाल में कोई छाप क्यों नहीं छोड़ पाए? क्यों उनकी सरकार का इकबाल शून्य पर है? क्या उनकी सरकार का सारा ध्यान तबादला, बहाली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीनें आवंटित करने आदि पर केंद्रित नहीं है? राज्य में बिजली का गहन संकट है, विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र ठप हैं या अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश में 12,700 मेगावाट प्रतिदिन बिजली की जरूरत है, सरकार केवल 10,700 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध करा पा रही है। बिजली चोरी और लीकेज के कारण सरकार को सालाना 7000 करोड़ रुपये की क्षति हो रही है। सड़कें टूटी-फूटी हैं या नदारद हैं। समझ में नहीं आता कि सड़कों में गढ्‌ढे हैं या गड्‌ढों में सड़क है।

बदायूं की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आए-दिन राज्य के किसी न किसी इलाके में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोज दिख रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बदायूं की घटना के बाद राज्य के प्रधान सचिव अनिल कुमार गुप्ता को स्थानांतरित करने में 6 दिन और स्थानीय थाना प्रभारी गंगा सिंह यादव का तबादला करने में 8 दिन का समय लगा। उत्तर प्रदेश में पहले थाना प्रभारी का चयन उसके कामकाज के रिकॉर्ड के आधार पर होता था। वर्ष 2012 में सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस व्यवस्था को बदल डाला।

सपा सरकार का पूरा ध्यान जातिवाद और मजहब की राजनीति पर है। आज उत्तर प्रदेश में कुल 1560 थाने हैं और उनमें से 800 थानों की कमान यादवों के हाथ में है। उनकी नियुक्ति जाति के आधार पर की गई या मेरिट पर, निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है। क्यों उनकी नियुक्ति उनके गृह जिले या पड़ोसी जिले में की गई? बदायूं की घटना में

स्थानीय पुलिस का निष्क्रिय रहना उसी का दुष्परिणाम है। दुष्कर्म और हत्या के तीन आरोपियों में से दो यादव हैं, कसूरवार स्थानीय पुलिस वालों में दो यादव हैं। क्या यह महज संयोग है? प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं व नेताओं की दबंगई आम बात है। इलाहाबाद के एक थाने में घुसकर स्थानीय सपा नेता गालीगलौज कर एक कैदी को छुड़ा ले जाता है और प्रशासन खामोश रहता है और यह कोई इकलौती घटना नहीं है। जो अधिकारी ऐसी अराजकता को चुनौती देने का दुस्साहस करता है उसे सपा सरकार प्रताड़ित करती है। दुर्गा शक्ति नागपाल इसका ज्वलंत उदाहरण है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा की तत्कालीन एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को कथित तौर पर एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवाने के आरोप में निलंबित कर दिया था। दुर्गा अवैध रेत खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कारण पहले से ही सपा नेताओं को चुभ रही थीं और रेत खनन माफियाओं के ही दबाव में उन्हें निलंबित किया गया। जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था वह सरकारी जमीन है। इसका अर्थ हुआ कि अवैध रेत खनन और सरकारी जमीन पर खड़ी की जा रही दीवार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल अपने संवैधानिक दायित्व का वहन कर रही थीं। स्वाभाविक तौर पर दुर्गा शक्ति के निलंबन से समाज में गलत संदेश गया। एक ओर जहां दबंग सपा नेता बेखौफ हुए वहीं निष्ठावान अधिकारियों का मनोबल गिरा। प्रशासन और पुलिस के वैसे अधिकारियों को गलत संदेश गया, जो अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हैं। सपा सरकार एक खास जाति और मजहब को तुष्ट कर राजपाट चलाना चाहती है। यह परिपाटी नई नहीं है। बसपा नेत्री मायावती 'जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी' का नारा लगाती थीं। राज्य के युवा मुख्यमंत्री से लोगों को स्वाभाविक तौर पर बड़ी अपेक्षाएं थीं कि वह जाति व मजहब विशेष के तुष्टीकरण की पारंपरिक लीक से हटकर सकारात्मक राजनीति करेंगे, किंतु ग्रेटर नोएडा, शामली और मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर उनके कामकाज का जो रवैया रहा उससे स्पष्ट है कि वह स्वतंत्र होकर काम कर पाने में असमर्थ हैं। कहने को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, किंतु सरकार में मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और इन सबके बेटों की धमक कम नहीं है। मुस्लिम चेहरे के नाम पर सपा ने आजम खां को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप रखे हैं। प्रशासन में आजम खां की तूती बोलती है। उनके ही अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण मुजफ्फरनगर के दंगे भयावह हुए। उनके आदेश पर प्रशासन आंखें मूंदे रहा, जिसके कारण लोगों के सब्र का बांध टूट गया।

जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से 50 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। वोट बैंक की राजनीति को पोषित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी और प्रशासन, दोनों का सांप्रदायिकरण किया। राज्य में फैली हिंसा उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन और पुलिस को अलिखित आदेश है कि किसी भी अपराध में कार्रवाई अपराध की गंभीरता को न देखकर अपराधी के मजहब और जाति को ध्यान में रखकर की जाए। यदि यही मापदंड रहा तो 'कानून के शासन' की व्यवस्था बेमानी है। आज

जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से 50 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। वोट बैंक की राजनीति को पोषित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी और प्रशासन, दोनों का सांप्रदायिकरण किया। राज्य में फैली हिंसा उसी का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन और पुलिस को अलिखित आदेश है कि किसी भी अपराध में कार्रवाई अपराध की गंभीरता को न देखकर अपराधी के मजहब और जाति को ध्यान में रखकर की जाए। यदि यही मापदंड रहा तो 'कानून के शासन' की व्यवस्था बेमानी है।

उत्तर प्रदेश में चारों ओर यदि अराजकता का साम्राज्य है तो इसके लिए यही मानसिकता जवाबदेह है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए राज्य में कानून एवं व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

जाति और मजहबी तुष्टीकरण की जगह समाज का समेकित विकास समय की मांग है और लोकसभा का वर्तमान जनादेश इस बदलते भारत को ही इंगित करता है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

(साभार- दै. जागरण)

निर्मल गंगा की नई आस

✍ हृदयनारायण दीक्षित

नदी नाद अद्वितीय है। अथर्ववेद के अनुसार नाद के कारण ही जल प्रवाह का नाम नदी पड़ा। अविरल, निर्मल, नदी नाद की गूंज में भारत की प्रज्ञा का विकास हुआ। यहां ढेर सारी नदियां उपास्य हैं। ऋग्वेद ने सरस्वती को 'नदीतमा अम्बितमा' गाया है। सिंधु आदि नदियों की भी प्रशंसा है, पर विश्वविख्यात नदी सूक्त गंगा से प्रारंभ होता है। प्रार्थना है कि गंगा यमुना आदि जलमाताएं हमारा कल्याण करें। गंगा भारत के मन का 'अनहदनाद' है। भारत ने उन्हें धरती पर सिर झुकाया तो आकाश की धवल नक्षत्रवलि को भी आकाश गंगा कहा। 861404 वर्ग किलोमीटर वाला गंगा बेसिन देश की सभी नदियों से बड़ा है और विश्व की नदियों में चौथा। कोई 2525 किमी लंबा यह क्षेत्र देश के पांच राज्यों-उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला है। गंगा तट पर 100 से ज्यादा बड़े नगर और हजारों गांव हैं। देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गंगा क्षेत्र में रहती है। पेयजल और सिंचाई आदि के साथ करोड़ों लोग गंगा स्नान से भी जुड़ते हैं, लेकिन गंगा का अस्तित्व संकट में है। गंगा में 30-35 हजार लाख लीटर कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। मोदी सरकार ने गंगा पोषण और निर्मल अविरल प्रवाह का संकल्प लिया है।

अविरल निर्मल गंगा प्रधानमंत्री मोदी की वरीयता है। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर मंत्रिसमूह बनाया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की मंत्री उमा भारती पहले से ही सक्रिय हैं। मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती, पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बैठकों का दौर जारी है। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में बना था। पर्यावरण, वित्त, नगर विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, विज्ञान के केंद्रीय मंत्री व गंगा क्षेत्र के पांच मुख्यमंत्री इसके सदस्य बनाए गए। प्राधिकरण रस्मी तौर पर हर साल दो बैठकें भी नहीं कर पाया। 2012 की एक बैठक में प्रधानमंत्री डॉ. सिंह ने कहा था कि गंगा को बचाने का समय हाथ से निकल रहा है। नए जनादेश ने उनके हाथ से गंगा बचाने का अवसर छीन लिया। गंगा संरक्षण के प्रश्न इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी राष्ट्रीय चिंता थे। उन्होंने 1979 में केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सर्वेक्षण के निर्देश दिए। काम कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 'केंद्रीय गंगा प्राधिकरण' बना। करोड़ों का बजट था। राजीव गांधी ने 1986 में वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान की घोषणा की, कहा 'गंगा आध्यामिकता की पहचान हैं। हम गंगा निर्मल करेंगे, लेकिन गंगा और मैली होती रही।'

861404 वर्ग किलोमीटर वाला गंगा बेसिन देश की सभी नदियों से बड़ा है और विश्व की नदियों में चौथा। कोई 2525 किमी लंबा यह क्षेत्र देश के पांच राज्यों-उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला है। गंगा तट पर 100 से ज्यादा बड़े नगर और हजारों गांव हैं। देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गंगा क्षेत्र में रहती है। पेयजल और सिंचाई आदि के साथ करोड़ों लोग गंगा स्नान से भी जुड़ते हैं, लेकिन गंगा का अस्तित्व संकट में है। गंगा में 30-35 हजार लाख लीटर कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। मोदी सरकार ने गंगा पोषण और निर्मल अविरल प्रवाह का संकल्प लिया है।

राजीव गांधी का गंगा एक्शन प्लान, प्रथम फेज, 1990 तक पूरा होना था। इसका समय 2001-2008 तक बढ़ाया गया। संसद की लोकलेखा समिति-2006, ने सरकारी कामकाज की कान खिंचाई की। उत्तर प्रदेश व बिहार की अधिकांश योजनाएं अधूरी थीं। गंगा एक्शन प्लान, फेज 2, में 615 करोड़ रुपये स्वीकृत थे। 270 परियोजनाएं थीं। संकल्पहीनता और भ्रष्टाचार के चलते एक्शन प्लान कबाड़ बना। काफी समय पहले एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में गंगा सहित विश्व की 10 बड़ी नदियों के अस्तित्व को खतरा बताया गया था। गंगा प्रदूषण और अविरल निर्मल प्रवाह को लेकर तमाम आंदोलन होते रहे, लेकिन सत्तातंत्र नहीं चेता। मोदी ने

वाराणसी में गंगा की आरती की, निर्मल गंगा का संकल्प लिया। प्रगाढ़ संकल्प विकल्पहीन होते हैं। गंगा जल संकल्प की बूंदें राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी है। गंगा का निर्मल किया जाना बहुत कठिन नहीं, लेकिन अविरल किया जाना कठिन है। अविरल जल प्रवाह का उद्गम गंगोत्री है। उत्तराखंड में तमाम बांध हैं। उनके अपने उपयोग हैं, लेकिन यही बांध अविरल प्रवाह में बाधक भी हैं। बांधों की उपयोगिता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा अविरल नहीं हैं। गंगा राष्ट्रीय प्रवाह है और अंतरराष्ट्रीय धरोहर। विश्व की किसी नदी को गंगा जैसा प्यार सम्मान नहीं मिला। अविरल प्रवाह राष्ट्रीय चिंता है। राच्य सरकारों को राष्ट्रीय चिंता के साथ जुड़ना ही चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी हार के बाद गंगा के प्रवाह को ठीक करने पर ही हास्यास्पद टिप्पणी की 'देखते हैं कि गंगा कैसे अविरल निर्मल होती है?' उत्तर प्रदेश, बिहार गंगा प्रदूषण का बड़ा क्षेत्र है। कानपुर के तमाम उद्योग अपना कचरा गंगा में छोड़ते हैं। कानपुर, उन्नाव के चमड़ा उद्योगों ने कुंभ के समय भी सरकारी निर्देश नहीं माने। सरकारें सभी उद्योगों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए विवश नहीं करती। यहां भ्रष्टाचार का मल अविरल है। राज्यों को गंगा प्रवाह के केंद्रीय संकल्प के साथ जुड़ना चाहिए।

गंगा में औद्योगिक कचरा और सीवर का प्रवाह मुख्य समस्या हैं। तटीय महानगरों/नगरों में गंगा के समानांतर कचरा/सीवेज आदि के लिए बड़े नाले बनाए जा सकते हैं। शहर की अंतिम सीमा पर दूषित जल शुद्धिकरण के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकते हैं। गंगा सहित सभी नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योगों/संस्थानों और व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए। नदियां पर्यावरण और प्राकृतिक जैव विविधता की संरक्षक हैं। सभ्यताओं का विकास नदी तट पर हुआ। मिस्न की सभ्यता नील नदी के तट पर उगी। मैसोपोटामिया सभ्यता का विकास यूपटिस और टाइग्रिस नदियों के तट पर हुआ। चीनी सभ्यता भी होयांग हो और मांगलिंग नदियों के तट पर विकसित हुई। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु आदि नदियों के तट पर ही विश्व मंगल की संस्कृति का विकास हुआ। गंगा स्वाभाविक ही भारत के मन का उल्लास हैं। जीवन में गंगा स्नान का आनंद और मृत्यु के बाद भी दो बूंद गंगा जल की प्यास भारतीय अभीप्सा है। मोदी ने ठीक ही गंगा से शुरुआत की है। मोदी विरल हैं। वह गंगा को अविरल और निर्मल बनाएंगे ही। यमुना सहित शेष नदियां भी इसी क्रम में पुनर्नवा तरुण होंगी।

हम भारत के लोग 'बहुधा यूरोपीय सभ्यता' की निंदा करते हैं। स्वयं को आध्यात्मिक और उन्हें भोगवादी बताते हैं। यूरोप की टेम्स, राइन और डेन्यूब नदियां भी प्रदूषण की शिकार थीं। इन नदियों के तट पर बड़े नगर हैं, कचरा इनमें भी जाता था। यूरोपीय नदियों को मां नहीं कहते। उन्होंने नदियों के पर्यावरणीय महत्व को जाना। सरकारों ने कार्यक्रम बनाए। नदियां निर्मल हो गईं। भारतवासी नदियों को मां कहते हैं, नीराजन, पूजन और पुण्याहवाचन करते हैं, लेकिन अधजले शव या बिना जले शव भी गंगा में फेंकते हैं। महानगरों का सीवेज गंगा सहित तमाम नदियों में गिरता है। गंगा मृत शरीर की सड़ांध ढोती है। कारखानों का विषाक्त जल पीती है।

मूलभूत प्रश्न है कि जो गंगा हमारे कारण ही मल ढोती है उन्हें निर्मल और अविरल करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्यों नहीं है? गंगावतरण भारत को प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। गंगा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण संकटग्रस्त नहीं है। गंगा संकट के दोषी हम सब ही हैं। यह संकट आधुनिक सभ्यता का संकट है और संस्कृतिविहीन समाज व राजनीति का भी संकट है। मोदी सरकार के संकल्प विश्वसनीय हैं, लेकिन गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है।■

(लेखक उप्र विधान परिषद के सदस्य हैं)

(साभार- दै. जागरण)

मूलभूत प्रश्न है कि जो गंगा हमारे कारण ही मल ढोती है उन्हें निर्मल और अविरल करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्यों नहीं है? गंगावतरण भारत को प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। गंगा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण संकटग्रस्त नहीं है। गंगा संकट के दोषी हम सब ही हैं। यह संकट आधुनिक सभ्यता का संकट है और संस्कृतिविहीन समाज व राजनीति का भी संकट है। मोदी सरकार के संकल्प विश्वसनीय हैं, लेकिन गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है।

बिहार में फिर जंगलराज

✍ संजीव कुमार सिन्हा

राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त, यह कहा नहीं जा सकता है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने हाथ मिला लिया। दोनों एक दूसरे के धुरविरोधी। तथ्य है कि जदयू का जन्म ही राजद के खिलाफ हुआ था। बार-बार सिद्धांत की दुहाई देनेवाले नीतीश कुमार ने सिद्धांतहीनता और अवसरवादी राजनीति का ऐसा परिचय दिया है, जिसकी चहुंओर निंदा हो रही है। जिस लालू यादव के जंगलराज के खात्मा का नारा देकर वे सत्ता में आए थे, अब उसी की शरण में उनका जाना बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। खुद के अहंकार को तुष्ट करने और स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार को संकट में धकेल दिया है।

गौरतलब है कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में बिहार में जहां भाजपानीत राजग की शानदार जीत हुई वहीं राजद और जदयू की करारी हार हुई। पिछली बार भाजपा के पास जहां 12 सीटें थीं वहीं इस बार उसकी सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ और उसे 22 सीटें मिलीं। भाजपा के सहयोगी दल लोजपा को 6 और रालोसपा को 3 सीटें मिलीं। जबकि राजद को चार, जदयू और कांग्रेस को दो-दो सीट और राकांपा को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा।

लोकसभा चुनाव में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद राजद और जदयू की नीदें उड़ी हुई हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन दोनों दलों को लगता है कि अब प्रदेश में अकेले भाजपा से मुकाबला कर पाना मुश्किल है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार को देखते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जदयू ने जीतन राम मांझी को विधायक दल का नेता चुना और उन्हें राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। विधानसभा में जदयू की यह सरकार अल्पमत में है और अब इसे बड़ा सहारा देते हुए अब तक विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी निभा रही राजद ने उसे बाहर से समर्थन देने की घोषणा कर दी है।

243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 115 विधायक हैं। इसके अलावा उसे 4 कांग्रेस और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। अब राजद के 21 विधायक भी जदयू के साथ हैं।

बिहार की स्थितियां बदल गई हैं। भाजपा ने समाज के सभी वर्गों के बीच अपना जनाधार मजबूत किया है। भाजपा के मजबूत होने से नीतीश कुमार डर गए हैं और उन्होंने अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया है। हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी राजद से राज्यसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। राज्यसभा चुनाव में हालांकि जदयू की जीत हुई लेकिन दोनों दलों को अपने विधायकों के बगावत का सामना करना पड़ा, कांग्रेस के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की, जबकि भाजपा के विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया।

जीत का एलान होते ही राजद नेता श्री लालू यादव ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने घोषणा कर दिया कि नीतीश कुमार के साथ आगे

भाजपा नेता बोले...

छोटे भाई और बड़े भाई के मिलाप पर कोई आश्चर्य नहीं है। यह तो पहले से ही गुपचुप तरीके से तय था। अब सबके सामने आ गया है। हम तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही कहते थे कि जदयू और राजद ने हाथ मिला लिया है और दोनों भाजपा गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। आज इनके समर्थन की घोषणा ने इस बात को पुष्ट कर दिया है।

- मंगल पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

फैसला अप्रत्याशित नहीं

राजद का फैसला अप्रत्याशित नहीं है। उसका जदयू के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के ही समय से हैं। दोनों दल डूब रहे हैं, इसलिए एक-दूसरे को बचाने में जुटे हैं। जनता राजद और जदयू के साथ नहीं है, इसलिए दोनों को इस दोस्ती से कोई फायदा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की तरह उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मिलेगा।

- नंदकिशोर यादव, नेता विपक्ष, विस

के गठबंधन की नींव पड़ चुकी है और राज्यसभा उपचुनाव तो शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने उन्हें और नीतीश कुमार को करीब ला दिया है। उन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजद से दोस्ती के सवाल पर कहा कि भाजपा को रोकने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भाजपा के खिलाफ अब व्यापक राजनीतिक गोलबंदी का विकल्प खुल गया है।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव कहते हैं कि पुराना जनता दल एक हुआ है। लालू प्रसाद ने हमारे दोनों उम्मीदवारों को समर्थन करके जदयू को जीत दिलाई। अंत भला तो सब भला।

जदयू और राजद का एक हो जाना जनादेश का मजाक है। यह अवसरवादी राजनीति है। लोगों ने नीतीश कुमार को लालू यादव के खिलाफ वोट दिया था क्योंकि बिहार की जनता लालू राज से मुक्ति चाहती थी। लोकसभा चुनाव में लालू यादव का पूरा परिवार चुनाव हार चुका है। पत्नी और बेटी चुनाव हार गई। और इधर, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा को नीतीश कुमार कमतर आंक रहे थे। लेकिन उन्हें अब लगने लगा है कि राज्य में भाजपा सबसे ताकतवर राजनीतिक दल है।

नीतीश कुमार का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। सिद्धान्त और आदर्श की वकालत करनेवाले नीतीश कुमार प्रदेश को जंगलराज की ओर ले जा रहे हैं और राजद एवं कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। लोहिया तथा जयप्रकाश के सिद्धान्त को नकार कर नीतीश कुमार सत्ता लोलुप बन गए हैं तथा बिहार की जनता के साथ

विश्वासघात दिवस

जीत के लिए नीतिश ने लालू के पांव पर रख दी पगड़ी : सुशील मोदी

भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा भाजपा सरकार गिराना नहीं चाहती है और न ही जनता पर चुनाव का बोझ ही डालना चाहती है। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा।

श्री मोदी पटना स्थित 17 जून को भारतीय नृत्यकला मंदिर में पार्टी द्वारा आयोजित विश्वासघात दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यदि सुशासन बाबू बने तो हमारी बदौलत, लेकिन हमें ही धोखा दे दिया। आज नीतीश कुमार ने जदयू सरकार बचाने के लिए लालू के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी है। जिस जंगलराज के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, आज उनसे ही भीख मांग रहे हैं। मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार से विकास की बात बेमानी है। यहां तो सरकार बचाने के लिए तमाम नैतिकता ताक पर रख दी गई है। दूसरे दलों के विधायकों से इस्तीफा करवाकर उन्हें मनोनयन कोटे से विधानपरिषद भेजा गया। ऐसा करके राज्यपाल को गुमराह किया गया। उन्होंने पूछा कि नीतीश बताएं कि क्या जनता ने कांग्रेस या लालू प्रसाद के समर्थन से सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया था?

विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि हमने नीतीश कुमार की हैसियत सात सीटों से बढ़ाकर यहां तक पहुंचाई। अब हम इन्हें फिर से वहीं पहुंचा देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार से दोस्ती पर लालू प्रसाद को चेताया और कहा कि यदि उन्होंने बबूल के पेड़ में खाद डालेंगे तो उसमें आम नहीं फलने वाला। कांटा ही होगा और उन्हें ही चुभेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडेय ने कहा कि नीतीश कुमार का काम सिर्फ सत्ता में बने रहना और अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखना है। इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।

समारोह को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सी. पी. ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, अरुण कुमार, सूरजनंदन कुशवाहा, सत्येन्द्र कुशवाहा, प्रमोद चन्द्रवंशी, संजय गुप्ता, गणेशजी, सुषमा साहू, हेमलता वर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संगठन महामंत्री नागेन्द्रजी, विधायक अनिल कुमार, संजय मयूख, अतुल कुमार, राकेश कुमार, राजीव रंजन भी उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता टी. एन. सिंह ने की। ■

विश्वासघात कर रहे हैं।

सवाल है कि क्या लालू प्रसाद से समर्थन मांगने के बाद भी नीतीश कुमार का स्वाभिमान और सिद्धांत बचा रह गया है? मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने दल-बदल कानून के नियमों को तोड़ कर राजद के 13 विधायकों को विधानसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता दिलायी। क्या यह संसदीय आचरण की नैतिकता के अनुकूल था? फिर जब राजद के समर्थन से सरकार बचाने की नौबत आयी, तब अलग गुटवाले फैसले को वापस कराया गया। नैतिकता तो दोनों बार तार-तार हुई। फिर भी उनकी जुबां पर नैतिकता की रट लगी रही। नीतीश कुमार द्वारा बार-बार सांप्रदायिकता का मुद्दा उछालना भी बेबुनियाद है क्योंकि वे 17 वर्षों तक भाजपा के साथ रहे, तब सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं था!

जंगलराज के पर्याय लालू यादव और अवसरवादी राजनीति के धरोहर नीतीश कुमार के एक साथ हो जाने से बिहार की जनता में आक्रोश और प्रबल होगा, क्योंकि लंबे समय के बाद बिहार में एनडीए शासन के दौरान विकास की किरणें फैल रही थीं लेकिन नीतीश कुमार ने अपने जिद्द के चलते बिहार को एक बार पुन: जंगलराज की ओर धकेल दिया है। निश्चित रूप से इसका खामियाजा जदयू-राजद को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। ■

विवेकपूर्ण वित्तीय अनुशासन के लिए कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि देश को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर लाने के लिए कड़े आर्थिक निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि विवेकपूर्ण वित्तीय अनुशासन के लिए जो कड़े कदम वह उठाने वाले हैं, वे न तो उनके और न ही उनकी पार्टी के हित में हैं, बल्कि देश के व्यापक हित में हैं।

प्रधानमंत्री तालीगाँव, गोवा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

श्री मोदी ने उन लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने गोवा राज्य में पार्टी की 100 प्रतिशत जीत में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि एक साल पहले, गोवा ही वह स्थान था जहाँ पार्टी ने आम चुनावों के लिए अभियान का नेतृत्व करने के लिए उन्हें चुना था, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद, दिल्ली के बाहर उनकी पहली यात्रा गोवा की ही है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि एक गैर-कांग्रेसी सरकार का पूर्ण बहुमत के साथ गठन किया गया है, और गठबंधन की राजनीति का युग समाप्त हो गया है। लोगों ने एक स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राजनीतिक दलों को, चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में, लोगों की उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इस चुनाव ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि लोगों ने जातिवाद, सांप्रदायिकता,भाई-भतीजावाद और परिवारवाद की राजनीति को पराजित कर दिया है। लोगों ने निर्णय ले लिया था कि सरकार का गठन सुरक्षा, समृद्धि प्रदान करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने, और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाना चाहिए। अबहमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें।

उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार सत्ता में रहते हुए भी लोगों से जुड़ी रहेगी और विकास की प्रक्रिया के लिए लोगों को सशक्त बनाने का काम करेगी। सरकार ने अपना काम अच्छी तरह से शुरू कर दिया है। दस वर्षों तक इस देश के लोगों ने दिल्ली में काम करने वाली सरकार को नहीं देखा है। हमारी सरकार सुशासन प्रदान करने के लिए स्पष्ट विवेक, स्पष्ट नीति और मजबूत नेतृत्व के साथ काम करेगी।

गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर, रक्षाराज्यमंत्री श्री राव इंदरजीत सिंह और प्रदेश भाजपा नेता भी बैठक में मौजूद थे। ■

ई-रिक्शों का हुआ उद्धार, करोड़ों को मिलेगा रोजगार

सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एलान किया है कि दिल्ली और देश के अन्य शहरों में सड़कों पर चल रहे ई-रिक्शों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार निश्चित क्षमता के ई-रिक्शों को मोटर वाहन एक्ट के दायरे से मुक्त करेगी। यही नहीं, ई-रिक्शा को रोजगार सृजन का माध्यम बनाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर दीन दयाल ई-रिक्शा योजना चलाई जाएगी जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री गडकरी दिल्ली के रामलीला मैदान में इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा) चालकों की एक रैली को संबोधित कर रहे थे।

दरअसल, दिल्ली में ई-रिक्शा की लगातार बढ़ रही संख्या के अंतर्गत लंबे समय से इन्हें कानून के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। इसी के विरोध में ई-रिक्शा चालकों द्वारा रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था।

श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली में चल रहे ई-रिक्शा को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे भारी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। इसके लिए 650 वाट तक के ई-रिक्शा को मोटर वाहन एक्ट के शिकंजे से बाहर लाया जाएगा। ऐसे ई-रिक्शा चालकों को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अब नगर निगम द्वारा किया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान नगर निगम ई-रिक्शा चालकों को पहचान पत्र देगा।

इतना ही नहीं, ई-रिक्शा का नाम अब दीन दयाल ई-रिक्शा होगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा में अब 25-50 किलो वजन ढोने की इजाजत भी होगी। दिल्ली में फिलहाल ई-रिक्शों में आठ-आठ सवारियां बैठाई जा रही हैं जो गलत है। श्री गडकरी ने ई-रिक्शा चालकों से अनुरोध किया कि वे चार से ज्यादा सवारियां नहीं बैठाएं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ई-रिक्शा के संबंध में नीति बनाने का आदेश देने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल में अधिसूचना जारी कर ई-रिक्शा को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद दिल्ली राज्य परिवहन मंत्रालय ने इन्हें जब्त करना शुरू कर दिया जिसके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इस मसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों उपराज्यपाल से मिले थे और ई-रिक्शा चालकों के हितों की रक्षा करने की बात कही थी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग ई-रिक्शा खरीदना चाहते हैं उन्हें बैंक द्वारा सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों को तीन फीसद की सालाना ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। साथ ही यह कर्ज उन्हें बिना किसी बैंक गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। ■